

उत्तर प्रदेश में बनेंगे 20 नए हाईटेक कारागार

चर्चा में क्यों?

20 मार्च, 2023 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार एक उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार वभाग ने अवगत कराया कि राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में नई जेलों के निर्माण का निर्णय लिया है।

प्रमुख बदि

- राज्य में नई जेलों के निर्माण के लिये प्रदेश के 11 ऐसे जिले चहिनति कयि गए हैं, जहाँ पर अभी कोई जेल नहीं है।
- जानकारी के अनुसार अमेठी, महोबा, कुशीनगर, चंदौली, औरैया, हाथरस, हापुड़, संभल, अमरोहा, भदोही और शामली में नई जेल बनेगी।
- आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने इसके अलावा एक केंद्रीय कारागार और नौ जिलों में दूसरी जेल के निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी है जबकि कुछ जेलों में बैरकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके लिये सरकार के निर्देश पर शासन ने कारागार वभाग को हरी झंडी देते हुए भारी भरकम बजट जारी कर दिया है।
- इन जेलों को वर्तमान परदृश्य को देखते हुए हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया जाएगा। इसके साथ ही नई जेलों के निर्माण का लक्ष्य दो से पाँच साल निर्धारित कयिा गया है।
- वदिति है कि वर्तमान में प्रदेश की केंद्रीय और जिला कारागार समेत कई कारागार में क्षमता से अधिक बंदी हैं। ऐसे में जेल मैनुअल द्वारा प्रदत्त सुवधिएँ उपलब्ध कराने और बंदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण को देखते हुए नई जेलों की आवश्यकता है।
- वभाग के वरषिठ अधिकारियों ने बताया था कि वर्तमान में सात केंद्रीय कारागार में 13,669 बंदियों की क्षमता है जबकि यहाँ पर 15,201 बंदी नरिद्ध हैं, जिसका अनुपात 111 प्रतशित है।
- इसी तरह 62 जिला कारागार में 49,107 बंदियों की क्षमता है, जिसके सापेक्ष 95,597 बंदी नरिद्ध हैं, जिसका अनुपात 194 प्रतशित है। वहीं 2 उप कारागार में 306 बंदियों की क्षमता है, जिसके सापेक्ष 664 बंदी नरिद्ध हैं, जिसका अनुपात 216 प्रतशित है। महिला केंद्रीय कारागार में 120 बंदियों की क्षमता है, जिसके सापेक्ष 148 बंदी नरिद्ध हैं, जिसका अनुपात 123 प्रतशित है।